गुरुवार, 23 जुलाई,2026

www.tvbharatvarsh.in

E-PAPER

कुल पृष्ठ–08

भारतीय कप्तान शुभमन गिल नंबर वन बल्लेबाज बनने के काफी करीब

Page-04

भारतवर्ष

सच्ची खबर, सीधे आपके लिए

'आवारापन 2' के गाने से मचा बवाल, अरिजित के संन्यास पर फिर छिड़ी बहस

Page-05

अनशन तोड़ने को तैयार सोनम वांगचुक

लेकिन सरकार के सामने रख दी बड़ी शर्त

- सोनम वांगचुक ने कहा कि यदि सरकार छात्रों पर कोई कानूनी कार्रवाई न करने और परीक्षा अनियमितताओं पर सार्थक कार्रवाई का आश्वासन दे, तो वे अपना 25 दिनों से जारी अनशन समाप्त कर देंगे।
- CJP ने वांगचुक से स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अनशन खत्म करने की अपील की और कहा कि परीक्षा न्याय की लड़ाई उनकी मांगें पूरी होने तक जारी रहेगी।

सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारों के समर्थक सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को पत्र लिखकर अपने अनिश्चितकालीन अनशन को समाप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण मांगें सामने रखी हैं। वांगचुक ने कहा है कि यदि सरकार उनकी प्रमुख मांगों पर स्पष्ट आश्वासन देती है, तो वह अपना अनशन समाप्त करने के साथ-साथ आंदोलन कर रहे छात्रों से भी फिलहाल प्रदर्शन रोककर सरकार के साथ संवाद शुरू करने की अपील करेंगे।सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा किए गए अपने संदेश में वांगचुक ने बताया कि हाल ही में अस्पताल में हुई मुलाकात के दौरान केंद्रीय मंत्रियों ने उनसे अनशन समाप्त करने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि बातचीत के दौरान उन्हें यह भरोसा दिया गया कि सरकार कथित परीक्षा अनियमितताओं और पेपर लीक मामलों से प्रभावित छात्रों के परिवारों के लिए उचित मुआवजे पर सकारात्मक विचार करेगी। साथ ही, संसद में इस मुद्दे पर सार्थक चर्चा कराने और जवाबदेही सुनिश्चित करने का प्रयास भी किया जाएगा।अपने पत्र में वांगचुक ने विशेष रूप से यह मांग उठाई कि आंदोलन में शामिल छात्रों और युवाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक या प्रतिशोधात्मक कानूनी कार्रवाई न की जाए। उनका कहना है कि इन युवाओं का एकमात्र उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करना है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार इस संबंध में स्पष्ट आश्वासन देती है, तो वह विश्वास के साथ अपना अनशन समाप्त कर देंगे।वांगचुक ने यह भी उम्मीद जताई कि आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल का अत्यधिक इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लाखों छात्रों की चिंताओं को गंभीरता से सुनना और उनका समाधान करना सरकार की जिम्मेदारी है।इस बीच, कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) ने भी सोनम वांगचुक से अपना अनिश्चितकालीन अनशन समाप्त करने की अपील की है। पार्टी ने एक सार्वजनिक पत्र जारी कर कहा कि वांगचुक के त्याग और संघर्ष ने देशभर के हजारों छात्रों को प्रेरित किया है। पार्टी ने उनसे अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का आग्रह करते हुए आश्वासन दिया कि परीक्षा अनियमितताओं और पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक उसकी प्रमुख मांगें पूरी नहीं हो जातीं।गौरतलब है कि सोनम वांगचुक पिछले 25 दिनों से कथित परीक्षा अनियमितताओं और जवाबदेही की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन पर हैं। हाल ही में आयोजित "संसद चलो" मार्च में भी देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में छात्र दिल्ली पहुंचे थे और आंदोलन के प्रति अपना समर्थन जताया था।

राहुल गांधी ने NEET मुद्दे पर सरकार को घेरा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को नीट-यूजी (NEET-UG) पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने लोक कल्याण मार्ग पर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन का बचाव करते हुए कहा कि जब देशभर में छात्र सड़कों पर उतरकर अपने भविष्य को लेकर आवाज उठा रहे हैं, तब विपक्ष का भी उनके साथ खड़ा होना जरूरी है। राहुल गांधी ने अन्य विपक्षी दलों से भी छात्रों के समर्थन में सड़कों पर उतरने की अपील की।नई दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि संसद इस तरह के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा का सबसे उपयुक्त मंच है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष की मांग के बावजूद संसद में नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा की अनुमति नहीं दी गई। राहुल गांधी के अनुसार, प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च करने से पहले विपक्षी नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर इस विषय पर चर्चा कराने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष ने सरकार से परामर्श करने की बात कही, लेकिन इसके बाद भी चर्चा नहीं कराई गई और पूरे मुद्दे को नजरअंदाज कर दिया गया।गौरतलब है कि मंगलवार को कांग्रेस ने लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित कई विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था। बाद में सभी नेताओं को रिहा कर दिया गया।

नीट विवाद पर राहुल गांधी का सरकार पर हमला, छात्रों पर कार्रवाई को बताया अन्याय

नीट (NEET) पेपर लीक मामले को लेकर देशभर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच राजनीतिक माहौल और गरमा गया है। दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को हिरासत में लिए जाने और जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस ने बुधवार को देशव्यापी प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगाया।दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया। उन्होंने नीट पेपर लीक मामले और छात्रों के आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ कठोर व्यवहार किया। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि छात्रों पर बल प्रयोग क्यों किया गया, जबकि वे अपने भविष्य और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग कर रहे थे।राहुल गांधी ने कहा कि नीट पेपर लीक प्रकरण से देश के करोड़ों छात्र और उनके परिवार प्रभावित हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इतने बड़े मामले के बावजूद अब तक किसी भी दोषी को सजा नहीं मिली है। उनके अनुसार, सरकार को छात्रों की चिंताओं का समाधान करने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है।गौरतलब है कि मंगलवार को राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव सहित कई विपक्षी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक आवास 7, लोक कल्याण मार्ग के निकट धरने पर बैठे थे। विपक्षी नेताओं की मांग थी कि नीट पेपर लीक मामले पर जवाबदेही तय की जाए और छात्रों की मांगों पर सरकार स्पष्ट रुख अपनाए।धरने के दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी से बातचीत की थी। हालांकि बातचीत के बाद भी विपक्षी नेता धरना स्थल से नहीं हटे। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने लगभग तीन घंटे बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव समेत कई नेताओं को हिरासत में ले लिया। बाद में देर रात सभी नेताओं को रिहा कर दिया गया।वहीं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देते हुए उन पर छात्रों के मुद्दे का राजनीतिक लाभ उठाने का आरोप लगाया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि राहुल गांधी संसद के मानसून सत्र के दौरान छात्रों को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रधान ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना देकर विपक्ष ने सुरक्षा नियमों और सार्वजनिक व्यवस्था की अनदेखी की है।इस मुद्दे को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव लगातार तेज होता जा रहा है।

नीट पेपर लीक के विरोध में पटना में बवाल, छात्रों और पुलिस के बीच झड़प

नीट (NEET) पेपर लीक मामले को लेकर देशभर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच बुधवार को बिहार की राजधानी पटना में भी स्थिति तनावपूर्ण हो गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर निकाले गए छात्र मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, पानी की बौछारें कीं और लाठीचार्ज का सहारा लिया।प्रदर्शन का आयोजन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन के छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) के बैनर तले किया गया था। छात्र नेता और भाकपा (माले) विधायक संदीप सौरभ के नेतृत्व में निकाले गए "लोक भवन मार्च" में बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए। प्रदर्शनकारी राज्यपाल आवास की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन गांधी मैदान के पास पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद स्थिति अचानक तनावपूर्ण हो गई। आरोप है कि कुछ प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। देखते ही देखते डाकबंगला चौराहा और आसपास का इलाका संघर्ष का केंद्र बन गया। सड़क पर ईंट-पत्थर बिखर गए और पुलिस की दो गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं।झड़प के दौरान कई पुलिसकर्मियों को चोटें आईं। पीरबहोर थाना के थाना प्रभारी भी घायल हो गए, जिनके सिर में चोट लगने की जानकारी सामने आई है। वहीं, कुछ समाचार चैनलों के पत्रकारों और कैमरामैन के साथ भी कथित मारपीट की घटनाएं सामने आईं, जिससे स्थिति और अधिक गंभीर हो गई।

संसद मार्च पर लाठीचार्ज मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस को हाईकोर्ट का नोटिस

20 जुलाई को संसद की ओर मार्च कर रहे छात्रों और युवाओं पर कथित लाठीचार्ज तथा आंसू गैस के इस्तेमाल के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। इस घटना को लेकर दायर कई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सभी संबंधित डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी।याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि संसद मार्च के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर अनावश्यक और अत्यधिक बल का प्रयोग किया। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सीसीटीवी फुटेज, बॉडी कैमरा रिकॉर्डिंग और अन्य डिजिटल सबूतों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सुरक्षित रखने का आदेश दिया है, ताकि जांच और सुनवाई के दौरान सभी तथ्य उपलब्ध रह सकें।गौरतलब है कि 20 जुलाई को जंतर-मंतर से शुरू हुआ यह मार्च नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में आयोजित किया गया था। 'कॉकरोच जनता पार्टी' (सीजेपी) के बैनर तले बड़ी संख्या में छात्र और युवा संसद की ओर बढ़ रहे थे। पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स के पास पहुंचने पर स्थिति तनावपूर्ण हो गई और प्रदर्शनकारियों तथा पुलिस के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई।घटना के बाद सोशल मीडिया पर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले छोड़े जाने और धक्का-मुक्की से जुड़े कई वीडियो और तस्वीरें वायरल हुईं। कुछ वीडियो में महिला प्रदर्शनकारियों के साथ कथित दुर्व्यवहार और बल प्रयोग के आरोप भी सामने आए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण था और पुलिस ने बिना किसी उचित कारण के बल प्रयोग किया।वहीं, दिल्ली पुलिस का दावा है कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ने और पथराव करने का प्रयास किया, जिससे पुलिसकर्मी भी घायल हुए। पुलिस के अनुसार, कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई थी।सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत मिले अधिकारों का उल्लंघन है। अदालत ने इन तर्कों पर गंभीरता से विचार करते हुए केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है।अब सभी की नजर 11 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर है, जहां इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया और तथ्यों की समीक्षा की जाएगी।

छात्रों की मांगें पूरी होने तक जारी रहेगा आंदोलन: सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि छात्रों की मांगें पूरी होने तक जंतर-मंतर पर चल रहा आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि संगठन अपने विरोध प्रदर्शन से पीछे नहीं हटेगा और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे सहित अन्य मांगों को लेकर संघर्ष जारी रखेगा।दीपके ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से भावुक अपील करते हुए उनका अनशन समाप्त करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि वांगचुक पिछले 25 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य और जीवन को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि देश को सोनम वांगचुक जैसे लोगों की जरूरत है और उनकी सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए।सरकार पर निशाना साधते हुए दीपके ने कहा कि जंतर-मंतर पर छात्र और युवा पिछले एक महीने से अधिक समय से शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान हुए पुलिस बल प्रयोग का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस और आरएएफ की कार्रवाई में छात्रों को नुकसान पहुंचा। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सरकार और अधिक छात्रों को नुकसान पहुंचाना चाहती है या उनकी मांगों पर निर्णय लेने के लिए तैयार है।दीपके ने कहा कि यदि सोनम वांगचुक अपना अनशन समाप्त भी कर देते हैं, तब भी आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रदर्शनकारी तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक उनकी प्रमुख मांगों पर कार्रवाई नहीं होती और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते।

ईरान युद्ध पर बढ़ता खर्च बना राजनीतिक मुद्दा ट्रंप प्रशासन विपक्ष के निशाने पर

पेंटागन ने बताया कि ईरान युद्ध में अब तक 18 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 430 सैनिक घायल हुए हैं। 7 जुलाई के बाद घायल हुए 100 सैनिकों में से 96 प्रतिशत दोबारा ड्यूटी पर लौट चुके हैं। बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच इस महीने की शुरुआत में हुआ युद्धविराम टूटने के बाद दोनों देशों के बीच रोजाना हमले जारी हैं।

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने मंगलवार को बताया कि ईरान के खिलाफ जारी युद्ध पर अमेरिका का अब तक का खर्च 37.5 अरब डॉलर (करीब ₹3.60 लाख करोड़) तक पहुंच गया है। उन्होंने वॉशिंगटन में कांग्रेस की एक सुनवाई के दौरान यह जानकारी दी। इस दौरान पीट हेगसेथ युद्ध को जारी रखने के लिए तत्काल अतिरिक्त फंडिंग की आवश्यकता बताई। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा कि 37.5 अरब डॉलर के इस अनुमान में अब तक हुए खर्च के साथ 30 सितंबर तक होने वाले संभावित खर्च भी शामिल हैं। हालांकि, पेंटागन ने यह स्पष्ट नहीं किया कि यह आंकड़ा किस आधार पर तैयार किया गया है। इससे पहले मार्च में एक रिपोर्ट के हवाले से बताया गया था कि युद्ध के शुरुआती छह दिनों में ही कम से कम 11.3 अरब डॉलर खर्च होने का अनुमान लगाया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने कांग्रेस से करीब 90 अरब डॉलर की अतिरिक्त फंडिंग मांगी थी, जिसमें अधिकांश राशि ईरान युद्ध से जुड़ी है। इस मांग पर कांग्रेस (अमेरिकी संसद) में बहस तेज हो गई है। नवंबर में होने वाले मिडटर्म चुनाव से पहले युद्ध और बढ़ते खर्च को लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार हमला बोल रहा है। सुनवाई के दौरान डेमोक्रेटिक सांसदों ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन पर युद्ध को लेकर पारदर्शिता नहीं बरतने का आरोप लगाया। वरिष्ठ डेमोक्रेट सदस्य पैटी मरे ने कहा कि राष्ट्रपति के बयान युद्ध को और बढ़ाने का संकेत देते हैं। इससे यह एक लंबा संघर्ष बन सकता है। वहीं, डेमोक्रेटिक सीनेटर किर्स्टन गिलिब्रैंड ने कहा कि प्रशासन के अलग-अलग बयान लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कभी युद्ध खत्म होने की बात कही जाती है और फिर नए सैन्य अभियान की घोषणा की जाती है। हेगसेथ ने चेतावनी दी कि यदि जल्द अतिरिक्त बजट नहीं मिला तो सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कटौती करनी पड़ सकती है। उन्होंने सांसदों से अतिरिक्त फंडिंग के साथ-साथ वित्त वर्ष 2027 के लिए 1.5 ट्रिलियन डॉलर के रक्षा बजट को भी मंजूरी देने की अपील की। उधर, अमेरिका के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैन केन ने स्थानीय समयानुसार मंगलवार को सीनेट से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 1.5 ट्रिलियन डॉलर के रक्षा बजट को मंजूरी देने की अपील की। उन्होंने कहा कि भविष्य की सैन्य चुनौतियों का सामना करने, महत्वपूर्ण तकनीकों में निवेश तेज करने और प्रतिद्वंद्वी देशों से आगे रहने के लिए अमेरिकी सशस्त्र बलों को इस फंडिंग की आवश्यकता है। उधर, अमेरिका के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैन केन ने स्थानीय समयानुसार मंगलवार को सीनेट से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 1.5 ट्रिलियन डॉलर के रक्षा बजट को मंजूरी देने की अपील की। उन्होंने कहा कि भविष्य की सैन्य चुनौतियों का सामना करने, महत्वपूर्ण तकनीकों में निवेश तेज करने और प्रतिद्वंद्वी देशों से आगे रहने के लिए अमेरिकी सशस्त्र बलों को इस फंडिंग की आवश्यकता है।

डोनाल्ड ट्रंप ने जेनेरिक दवाओं के लिए एक नई टैरिफ पॉलिसी लागू की

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इंपोर्ट की जाने वाली जेनेरिक दवाओं के लिए एक नई टैरिफ पॉलिसी लागू की है। इस पॉलिसी में ड्यूटी (टैक्स) को धीरे-धीरे बढ़ाने की योजना है, ताकि दवा बनाने का काम वापस अमेरिका में शुरू हो सके। इस योजना के तहत, इंपोर्ट की जाने वाली जेनेरिक दवाओं पर अगले दो साल तक कोई टैरिफ नहीं लगेगा, लेकिन 2028 से इन पर भारी ड्यूटी लगाई जाएगी। अपने 'ट्रुथ सोशल' प्लेटफॉर्म पर इस फैसले की घोषणा करते हुए ट्रंप ने कहा कि इस पॉलिसी का मकसद दवा कंपनियों को विदेश में प्रोडक्शन पर निर्भर रहने के बजाय अमेरिका में ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह प्रस्ताव घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने और इंपोर्ट की जाने वाली दवाओं पर निर्भरता कम करने की उनकी बड़ी रणनीति का एक नया कदम है। ट्रम्प की घोषणा के अनुसार, आयातित जेनेरिक दवाओं पर 1 अगस्त, 2026 से दो साल की अवधि के लिए शून्य प्रतिशत टैरिफ लागू रहेगा। इस संक्रमणकालीन अवधि के समाप्त होने के बाद, टैरिफ एक वर्ष के लिए 100 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा और उसके बाद 200 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा। ट्रंप ने लिखा अगस्त, 2026 से, संयुक्त राज्य अमेरिका में लाई जाने वाली सभी जेनेरिक दवाओं पर दो साल की अवधि के लिए शून्य प्रतिशत टैरिफ लागू रहेगा, जिसके बाद टैरिफ एक वर्ष की अवधि के लिए 100% तक बढ़ जाएगा और उसके बाद 200% तक बढ़ जाएगा।

उत्तराखंड सरकार राज्य में एक संस्कृत आयोग बनाने की योजना बना रही

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

उत्तराखंड सरकार राज्य में संस्कृत भाषा को संरक्षित और समृद्ध करने तथा इसके इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए एक संस्कृत आयोग बनाने की योजना बना रही है। सरकार ने इस आयोग के लिए देश भर के संस्कृत विद्वानों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं, विश्वविद्यालयों, गुरुकुलों और संस्कृत प्रेमियों से 10 अगस्त तक ईमेल के ज़रिए सुझाव मांगे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड की विरासत में संस्कृत का खास स्थान है। उन्होंने इस भाषा को आज के समय के हिसाब से प्रासंगिक बनाने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। धामी ने कहा कि संस्कृत सिर्फ़ एक भाषा नहीं, बल्कि भारत की ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक विरासत की नींव है। राज्य सरकार इसे आम लोगों तक पहुँचाने और समय के अनुरूप इसे एक नई पहचान दिलाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। संस्कृत शिक्षा सचिव दीपक कुमार ने कहा कि उत्तराखंड ने 2010 में संस्कृत को दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा देकर एक अहम कदम उठाया था। उन्होंने बताया कि धामी ने दिसंबर 2025 में हरिद्वार में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन में संस्कृत आयोग की ज़रूरत पर ज़ोर दिया था। 15 जुलाई को हुई एक बैठक में आयोग बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। अधिकारियों ने बताया कि आयोग से संस्कृत शिक्षा और रिसर्च, पुरानी पांडुलिपियों को सुरक्षित रखने और उन्हें डिजिटल बनाने, भारतीय ज्ञान परंपराओं और वैदिक व शास्त्रीय अध्ययन के लिए काम करने की उम्मीद है। यह संस्कृत पर आधारित स्किल डेवलपमेंट और रोज़गार के मौकों पर ध्यान देगा। इस पैनल का मकसद प्रशासन और तकनीकी क्षेत्रों में संस्कृत के इस्तेमाल को बढ़ाना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व डिजिटल मीडिया में इस भाषा की संभावनाओं को तलाशना है।

भारत ने अफगानिस्तान पर UNSC के प्रतिबंधों की समीक्षा की मांग की

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में अफगानिस्तान की जमकर तरफदारी की है। उसने अफगानिस्तान पर लगे संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों पर फिर से विचार करने का आग्रह किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने यूएनएससी की बैठक में कहा कि अफगानिस्तान के राजनीतिक हालात काफी बदल गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि इसलिए मौजूदा संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध व्यवस्था पर फिर से विचार करना जरूरी हो गया है। भारत का यह बयान तब आया है, जब पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान पर हवाई हमले कर रहा है। पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि मौजूदा सजा वाले उपायों का असर खत्म हो गया है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अफगानिस्तान के साथ बातचीत के लिए नया तरीका अपनाने का आग्रह किया। हरीश ने अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के हवाई हमलों की भी निंदा की। उन्होंने 'यूनाइटेड नेशंस असिस्टेंस मिशन इन अफगानिस्तान' (UNAMA) की उन रिपोर्टों का जिक्र किया जिनमें इन हमलों की वजह से बड़ी संख्या में आम नागरिकों के हताहत होने की बात कही गई थी। भारतीय प्रतिनिधि ने पाकिस्तान पर अफगानिस्तान के साथ व्यापार और ट्रांजिट पर पाबंदियां लगाने का भी आरोप लगाया और उन्हें हटाने की मांग की। दरअसल, अफगानिस्तान चारों ओर से जमीन से घिरा देश है। वह लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए पाकिस्तान पर निर्भर है। हालांकि पाकिस्तान उसी का फायदा उठाकर अफगानिस्तान पर दबाव बना रहा है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान सीमा को पूरी तरह से बंद कर दिया है। इस कारण माल ढुलाई के अलावा लोगों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है।

नेपाल में बुधवार तड़के 4.2 तीव्रता का भूकंप आया

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

नेपाल में बुधवार तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे कई इलाकों में लोगों के बीच कुछ समय के लिए दहशत का माहौल बन गया। राष्ट्रीय भूकंप निगरानी एवं अनुसंधान केंद्र (NEMRC) के अनुसार, भूकंप स्थानीय समयानुसार सुबह 4:40 बजे आया। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.2 दर्ज की गई। भूकंप का केंद्र राजधानी काठमांडू से लगभग 900 किलोमीटर पश्चिम में स्थित बाजहांग जिले के कोटदेवाल क्षेत्र के आसपास था।भूकंप के झटके केवल बाजहांग तक सीमित नहीं रहे, बल्कि पड़ोसी जिलों बाजुरा और दार्चुला में भी महसूस किए गए। सुबह के समय आए इन झटकों के कारण कई लोग घरों से बाहर निकल आए। हालांकि, स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन एजेंसियों ने राहत की खबर देते हुए बताया कि अब तक किसी भी प्रकार के जान-माल या संपत्ति के नुकसान की सूचना नहीं मिली है।नेपाल हाल के दिनों में लगातार भूगर्भीय गतिविधियों का सामना कर रहा है। पिछले सप्ताह भी पश्चिमी नेपाल के लुंबिनी प्रांत के रुकुम पूर्व जिले में रिक्टर पैमाने पर 5.0 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया था। विशेषज्ञों का मानना है कि हिमालयी क्षेत्र भूगर्भीय दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है, जिसके कारण यहां समय-समय पर भूकंप आते रहते हैं।बुधवार को केवल नेपाल ही नहीं, बल्कि भारत और पड़ोसी देश म्यांमार में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। भारत के अरुणाचल प्रदेश के बिचोम क्षेत्र में सुबह 9:37 बजे 2.8 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। इसका केंद्र जमीन से 30 किलोमीटर की गहराई में था। हालांकि इसकी तीव्रता कम होने के कारण किसी नुकसान की सूचना नहीं मिली।इसके लगभग आधे घंटे बाद, सुबह 10:11 बजे मध्य प्रदेश के कटनी जिले में 3.6 तीव्रता का भूकंप आया। इसका केंद्र जमीन से केवल 10 किलोमीटर की गहराई पर था, जो दिनभर दर्ज किए गए भूकंपों में सबसे कम गहराई वाला था। वहीं, म्यांमार में भी सुबह 11:48 बजे 3.6 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया।फिलहाल नेपाल, भारत और म्यांमार में आए इन भूकंपों से किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है, लेकिन लगातार हो रही भूगर्भीय गतिविधियों ने विशेषज्ञों और प्रशासन की सतर्कता बढ़ा दी है।

संपादक की कलम से

संसद में संवाद जरूरी, गतिरोध नहीं:

लोकतंत्र में संसद केवल कानून बनाने का मंच नहीं, बल्कि जनता के सवालों और सरकार की जवाबदेही का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। ऐसे में नीट-यूजी पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दे पर संसद का लगातार ठप रहना चिंता का विषय है। छात्रों और अभिभावकों के मन में परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को लेकर जो सवाल खड़े हुए हैं, उनका जवाब सदन में व्यापक और सार्थक चर्चा के माध्यम से ही दिया जा सकता है।विपक्ष का यह अधिकार है कि वह सरकार से जवाब मांगे और जिम्मेदारी तय करने की मांग करे। वहीं सरकार का दायित्व है कि वह मामले में उठाए गए कदमों, जांच की स्थिति और भविष्य की सुधार योजनाओं को संसद के सामने रखे। लेकिन जब चर्चा की बजाय केवल हंगामा और आरोप-प्रत्यारोप हावी हो जाते हैं, तब सबसे बड़ा नुकसान लोकतांत्रिक प्रक्रिया और जनता के हितों का होता है।नीट पेपर लीक विवाद केवल एक परीक्षा का मामला नहीं है, बल्कि यह करोड़ों युवाओं के भविष्य और देश की शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता से जुड़ा प्रश्न है। ऐसे मुद्दे पर संसद में गंभीर बहस होनी चाहिए, ताकि जिम्मेदारी तय होने के साथ-साथ भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस सुधारों पर भी सहमति बन सके।संसद में गतिरोध किसी भी पक्ष की जीत नहीं है। यदि विपक्ष जवाबदेही चाहता है तो उसे चर्चा में भाग लेना चाहिए, और यदि सरकार अपने कदमों को सही मानती है तो उसे भी हर प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। लोकतंत्र की मजबूती टकराव से नहीं, बल्कि संवाद और बहस से होती है।आज आवश्यकता इस बात की है कि राजनीतिक दल अपने-अपने रुख से ऊपर उठकर छात्रों और देश के व्यापक हित को प्राथमिकता दें। संसद का समय बहुमूल्य है और जनता की अपेक्षा है कि उसके प्रतिनिधि समाधान खोजें, न कि केवल गतिरोध पैदा करें। नीट विवाद पर पारदर्शी चर्चा और ठोस निर्णय ही इस विश्वास संकट को दूर कर सकते हैं।

नीट मुद्दे पर संसद में जारी गतिरोध तीसरे दिन भी दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित

नीट-यूजी 2024 परीक्षा में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोपों के बाद देशभर में छात्रों और विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन किए। विपक्ष इस मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है, जबकि केंद्र सरकार का कहना है कि उसने मामले की जांच के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं।

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

संसद के मॉनसून सत्र में बुधवार को लगातार तीसरे दिन भी गतिरोध जारी रहा। विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार-बार बाधित हुई और अंततः दोनों सदनों को अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दिया गया। विपक्ष केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है, जबकि सरकार का कहना है कि वह नीट-यूजी प्रश्नपत्र लीक मामले समेत सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार शुरू से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए "सौ प्रतिशत तैयार" है। उन्होंने सदन को बताया कि सरकार ने कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के नेताओं को भी इस संबंध में अपनी सहमति से अवगत कराया था। रिजिजू ने आरोप लगाया कि विपक्ष चर्चा से बचने के लिए बहाने बना रहा है और जानबूझकर सदन की कार्यवाही में बाधा डाल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों और युवाओं के भविष्य से जुड़े इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर उठाए गए कदमों की जानकारी देश और संसद के सामने रखने के लिए प्रतिबद्ध है।वहीं, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार के रुख को खारिज करते हुए कहा कि नीट मामले पर निष्पक्ष और सार्थक चर्चा तभी संभव है जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहले अपने पद से इस्तीफा दें। विपक्ष का आरोप है कि नीट परीक्षा में हुई कथित अनियमितताओं और पेपर लीक मामले की नैतिक जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री को लेनी चाहिए।लोकसभा में विपक्षी सदस्यों के लगातार विरोध और नारेबाजी के कारण सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी। बाद में इसे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। इसी दौरान तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को सदन में कुछ महिला सदस्यों के प्रति कथित अभद्र व्यवहार और दुर्व्यवहार के मामले में मौजूदा सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया।राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष, विशेष रूप से इंडिया गठबंधन, पर संसद की मर्यादा को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष का व्यवहार गैर-जिम्मेदाराना है और उसकी गतिविधियां लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत हैं। नड्डा ने कहा कि लगातार हंगामा कर विपक्ष संसद की गरिमा को ठेस पहुंचा रहा है और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बाधित कर रहा है।नीट पेपर लीक मामले को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच जारी टकराव के चलते संसद का मॉनसून सत्र लगातार प्रभावित हो रहा है। दोनों पक्ष अपने-अपने रुख पर कायम हैं, जिससे गतिरोध समाप्त होने के संकेत फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं।

विपक्षी दलों के कई सांसदों ने संसद पहुंचकर काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

छात्र प्रदर्शनकारियों और सांसदों के साथ कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में बुधवार को विपक्षी दलों के कई सांसदों ने संसद पहुंचकर काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के सांसद इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार छात्र आंदोलनों और देश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को ठीक तरीके से नहीं संभाल रही है। प्रदर्शनकारियों ने मकर द्वार के सामने एकजुट होकर अपना विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस सांसद के सुरेश ने कहा कि काले कपड़े पहनने का फैसला मंगलवार को हुए प्रदर्शन के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अन्य सांसदों के साथ पुलिस की कथित सख्ती के विरोध में लिया गया है। उन्होंने कहा, 'आज हम सभी काले कपड़े पहनकर आए हैं, क्योंकि हम मकर द्वार के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। यह प्रदर्शन कल विपक्ष के नेता और अन्य सांसदों के साथ पुलिस द्वारा की गई कथित बर्बर कार्रवाई के खिलाफ है।' आरजेडी सांसद संजय यादव ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में बार-बार पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं और बेरोजगारी पिछले 50 वर्षों के सबसे ऊंचे स्तर पर है। उन्होंने आरोप लगाया कि पारदर्शिता की मांग कर रहे युवाओं पर सरकार

दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। यादव ने कहा कि सरकार की खराब नीतियों के कारण करोड़ों छात्र और युवा बेरोजगार हैं और उनका भविष्य अनिश्चित हो गया है। इससे पहले मंगलवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने कई राज्यों में प्रदर्शन किया था। यह प्रदर्शन राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य नेताओं को दिल्ली में हिरासत में लिए जाने के विरोध में किया गया था। कांग्रेस ने सोमवार को सेंट्रल दिल्ली में छात्र संगठन सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई की भी निंदा की थी। इसके बाद तिरुवनंतपुरम, गुवाहाटी, जबलपुर और भुवनेश्वर समेत कई शहरों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए और उस पर लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शनों को दबाने का आरोप लगाया। मंगलवार को कांग्रेस नेताओं ने राजाजी मार्ग से लोक कल्याण मार्ग तक मार्च निकाला था। उनकी मांग थी कि कथित परीक्षा पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय की जाए, छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई की जांच हो और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कई अन्य नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था।

मनोज जरांगे पाटिल ने दिल्ली के जंतर-मंतर पहुंचकर सीजेपी आंदोलन का समर्थन किया

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

नीट पेपर लीक मामले को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के बैनर तले दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे आंदोलन को अब देशभर से समर्थन मिलने लगा है। सोमवार को 'संसद मार्च' के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद आंदोलन और तेज हो गया है। विपक्षी दलों के साथ-साथ कई सामाजिक संगठनों ने भी प्रदर्शनकारी छात्रों का समर्थन किया है। इसी बीच मराठा आरक्षण आंदोलन के प्रमुख नेता मनोज जरांगे पाटिल बुधवार को जंतर-मंतर पहुंचे और CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके से मुलाकात कर आंदोलन को अपना समर्थन दिया। जंतर-मंतर पर छात्रों को संबोधित करते हुए मनोज जरांगे ने कहा कि शांतिपूर्ण आंदोलन की ताकत सबसे बड़ी होती है। यहां मौजूद छात्रों और युवाओं को किसी भी हालत में विरोध-प्रदर्शन वाली जगह से नहीं हटना है, नहीं तो सरकार इस आंदोलन को कुचल देगी। उन्होंने कहा, "जब मैं अपने गांव अंतरवली में आंदोलन कर रहा था, तब महिलाओं और बुजुर्गों पर भी जानलेवा हमला किया गया था। सरकार ने हम पर गोलियां तक चलवाई थीं। मैं सभी छात्रों से कहना चाहता हूं कि यह जगह मत छोड़िए। पूरा देश आपके साथ खड़ा है। अगर आप यहां से हट गए तो यह आंदोलन खत्म कर दिया जाएगा। हमने साबित किया है कि शांतिपूर्ण आंदोलन में कितनी ताकत होती है।" मनोज जरांगे ने कहा कि सरकार जनता के वोट से बनी है और वही आज छात्रों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा, "सरकार को हमने चुना है। हमारे माता-पिता, गांव, जिले और राज्य के लोगों ने इन्हें वोट दिया है, लेकिन आज यही सरकार छात्रों पर अत्याचार कर रही है। छात्रों और गरीब लोगों में इतनी ताकत है कि वे सरकार को सत्ता से बाहर कर सकते हैं। अगर आगे किसी भी तरह की परेशानी आई तो हम सभी आपके साथ खड़े रहेंगे। पूरा महाराष्ट्र और पूरा देश आपके समर्थन में है।" मनोज जरांगे ने जंतर-मंतर पर मराठी भाषा में अपना संबोधन दिया। वहां मौजूद अन्य राज्यों के लोगों तक उनका संदेश पहुंचाने के लिए अभिजीत दीपके ने उनके भाषण का हिंदी में अनुवाद किया। दीपके ने कहा, "शायद आप इन्हें नहीं जानते होंगे, पर यह बहुत बड़ी ताकत हैं, आप इंटरनेट पर इनके बारे में जान सकते हैं।" अभिजीत दीपके ने बताया कि मनोज जरांगे ने एक वीडियो देखा था,

जिसमें एक छात्रा रो रही थी और आसपास छात्रों पर लाठियां बरस रही थी। वह वीडियो देखने के बाद ही उन्होंने दिल्ली आने का फैसला किया। उनके आने से आज आंदोलन को बड़ी ताकत मिली है।"

संसद का प्रश्नकाल: कैसे पूछे जाते हैं सवाल और हर प्रश्न का जवाब क्यों नहीं देती सरकार?

देश में संसद का मानसून सत्र जारी है और इस दौरान प्रश्नकाल (Question Hour) एक बार फिर चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रश्नकाल भारतीय संसदीय व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में से एक है। इसके माध्यम से सांसद जनता से जुड़े मुद्दों, सरकारी नीतियों और प्रशासनिक कार्यों पर सरकार से सवाल पूछते हैं। यह व्यवस्था लोकतंत्र को मजबूत बनाने के साथ-साथ सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने का भी एक प्रभावी माध्यम मानी जाती है।संसद की कार्यवाही में लोकसभा की बैठक का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए निर्धारित होता है। इस दौरान सांसद विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से जुड़े मामलों पर प्रश्न पूछ सकते हैं। संसद की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, सवाल पूछना सांसदों का एक महत्वपूर्ण संसदीय अधिकार है। इसके जरिए निर्वाचित जनप्रतिनिधि सरकार के कार्यों की समीक्षा करते हैं और जनता की चिंताओं को सीधे सदन में उठाते हैं।प्रश्नकाल का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह शासन में पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। सांसदों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देते समय संबंधित मंत्री को अपने विभाग के कामकाज, योजनाओं और निर्णयों की जानकारी देनी होती है। इस प्रक्रिया से सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की सार्वजनिक समीक्षा संभव हो पाती है। कई बार प्रश्नकाल के दौरान ऐसी जानकारियां सामने आती हैं जो प्रशासनिक सुधारों और नीति निर्माण में भी मददगार साबित होती हैं।संसद में मुख्य रूप से तीन प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला, तारांकित प्रश्न (Starred Question), जिसका उत्तर संबंधित मंत्री को सदन में मौखिक रूप से देना होता है। ऐसे प्रश्नों पर सांसद पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। दूसरा, अतारांकित प्रश्न (Unstarred Question), जिसका उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है और इसमें पूरक प्रश्नों की अनुमति नहीं होती। तीसरा, शॉर्ट नोटिस प्रश्न (Short Notice Question), जिसे किसी अत्यंत महत्वपूर्ण और तात्कालिक जनहित के विषय पर कम समय की सूचना देकर पूछा जा सकता है।हालांकि, संसद में पूछे गए सभी प्रश्न स्वीकार नहीं किए जाते। लोकसभा की कार्य-प्रक्रिया और कामकाज के संचालन से संबंधित नियमों के तहत प्रश्नों की जांच की जाती है। सामान्यतः वे प्रश्न स्वीकार किए जाते हैं जो सार्वजनिक महत्व के हों, सरकारी नीतियों या किसी मंत्री के कार्यों से जुड़े हों और जिनसे तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त की जा सके।कई बार सरकार किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देती या प्रश्न को स्वीकार नहीं किया जाता। इसके पीछे संसदीय नियम होते हैं। यदि प्रश्न में व्यक्तिगत आरोप, राय, तर्क, काल्पनिक स्थिति या मानहानिकारक भाषा का प्रयोग किया गया हो तो उसे अस्वीकार किया जा सकता है। इसके अलावा, अदालत में विचाराधीन मामलों (सब-ज्यूडिस) से जुड़े प्रश्नों पर भी जवाब देने से परहेज किया जाता है। ऐसे प्रश्न जो अस्पष्ट हों, किसी विशेष उत्तर की ओर संकेत करते हों या जिनकी जानकारी पहले से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो, उन्हें भी स्वीकार नहीं किया जाता।विशेषज्ञों का मानना है कि प्रश्नकाल संसद की आत्मा माना जाता है। यह न केवल सरकार को जवाबदेह बनाता है, बल्कि जनता की समस्याओं और मुद्दों को राष्ट्रीय मंच पर उठाने का एक सशक्त माध्यम भी है। यही कारण है कि भारतीय लोकतंत्र में प्रश्नकाल की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है।

आर्ट्स से ग्रेजुएशन करने वाले कैंडिडेट्सनेशनल बुक ट्रस्ट में नौकरी पाने का अवसर

आर्ट्स से ग्रेजुएशन करने वाले कैंडिडेट्स जो अच्छी जॉब ढूंढ रहे हैं, उनके लिए नेशनल बुक ट्रस्ट में नौकरी पाने का अवसर है। यहां यंग प्रोफेशनल की हायरिंग निकली है। जिसके लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन लिए जा रहे हैं। अगर आप एलिजिबल हैं, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। मंथली सैलरी अच्छी मिलेगी। ध्यान रखें कि एप्लिकेशन फॉर्म ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन आपको ट्रस्ट को भेजना होगा। इसके लिए यहां फॉर्म के फॉर्मेट के साथ आवेदन करने का पूरा तरीका भी बताया जा रहा है। नेशनल बुक ट्रस्ट, शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक स्वायत्त संगठन है। जो अच्छी पुस्तकों के प्रकाशन और उन्हें किफायती कीमतों पर लोगों तक पहुंचाता है। इसके अलावा देशभर में पुस्तक मेलों और साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन भी ट्रस्ट समय-समय करता रहता है। कैंडिडेट्स को यहीं काम करना होगा। यंग प्रोफेशनल की यह भर्ती एग्जीबिशन के लिए की जा रही है। यंग प्रोफेशनल की नियुक्ति पूरी तरह से कॉन्ट्रेक्ट बेस पर मैनपावर एजेंसी के जरिए की जा रही है। शुरुआत में तीन महीने के लिए काम की अवधि तय की जाएगी, जिसे नेशनल बुक ट्रस्ट अपनी जरुरत के मुताबिक आगे बढ़ा सकेगा। इस दौरान इस पोस्ट पर जिन उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। उन्हें महीने का 60000-70000 रुपये तक वेतन मिलेगा। जो अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए चुने जाते हैं, उन्हें साक्षात्कार के समय अपनी सभी ओरिजनल दस्तावेज दिखाने होंगे।

अफगान टीम को मिला नया कप्तान रहमत शाह जुरमती संभालेंगे कमान

भारतीय कप्तान शुभमन गिल नंबर वन बल्लेबाज बनने के काफी करीब

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बुधवार को वनडे बल्लेबाजों की ताज़ा रैंकिंग जारी कर दी है। टॉप 5 में तीन भारतीय बल्लेबाज बने हुए हैं। भारतीय कप्तान शुभमन गिल नंबर वन बल्लेबाज बनने के काफी करीब आ गए हैं। वहीं इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट को भी काफी फायदा हुआ है। आईसीसी की ताजा रैंकिंग में न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाज डेरिल मिशेल 802 अंकों के साथ पहले स्थान पर हैं। शुभमन गिल दूसरे नंबर पर हैं। गिल और मिशेल की रेटिंग में सिर्फ एक अंक का अंतर है। विराट कोहली 767 रेटिंग अंक के साथ तीसरे स्थान पर हैं, जबकि लॉर्ड्स में हाल ही में 138 रन की पारी खेलने वाले रोहित शर्मा 758 रेटिंग अंक के साथ चौथे स्थान पर हैं। अफगानिस्तान के इब्राहिम जादरान 712 रेटिंग अंक के साथ पांचवें स्थान पर हैं। पाकिस्तान के बाबर आजम और आयरलैंड के हैरी टैक्टर को 1-1 स्थान का फायदा हुआ है। दोनों छठे और सातवें स्थान पर हैं। बाबर के 689 अंक और टैक्टर के 679 अंक हैं। भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे इंग्लैंड के जो रूट को 4 स्थान का फायदा हुआ है। रूट शीर्ष 10 खिलाड़ियों में वापस आ गए हैं और आठवें नंबर पर हैं। उनके 674 रेटिंग अंक हैं। वेस्टइंडीज के शे होप को तीन स्थान का घाटा हुआ है, वे 672 रेटिंग अंक के साथ नौवें नंबर पर हैं। श्रीलंका के चरिथ असलांका एक अंक के नुकसान के बावजूद 659 रेटिंग अंक के साथ दसवें स्थान पर हैं। वनडे फॉर्मेट के शीर्ष दस गेंदबाजों की बात करें तो अफगानिस्तान के राशिद खान 682 रेटिंग अंक के साथ पहले और पाकिस्तान के अबरार अहमद 675 रेटिंग अंक के साथ दूसरे स्थान पर हैं। इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर को एक स्थान का फायदा हुआ है, वह 649 रेटिंग अंक के साथ तीसरे स्थान पर आ गए हैं। न्यूजीलैंड के मिशेल सेंटनर को तीन स्थान का फायदा हुआ है। सेंटनर 645 रेटिंग अंक के साथ चौथे स्थान पर हैं।

ललित मोदी का भारत वापस लौटने का ऐलान

IPL के फाउंडर और पहले चेयरमैन ललित मोदी को लेकर बड़ी ख़बर सामने आई है। ललित मोदी को 21 जुलाई को कोर्ट से क्लीनचिट मिल गई। इसके बाद ललित मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने भारत वापस लौटने का ऐलान कर दिया है। ललित मोदी ने कहा कि वह कल आए फैसले से बहुत खुश हैं। सच में, यह दिन बहुत अच्छा रहा है। उन्होंने 16 साल तक लड़ाई लड़ी और मीडिया और बाकी सभी लोगों से जो कुछ भी कहा, वह आखिरकार सच साबित हुआ। उन्हें बहुत खुशी है कि ट्रिब्यूनल ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया है। उन्हें सिर्फ IPL की भलाई की चिंता थी और किसी चीज की नहीं। वह उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अब वह चैप्टर पीछे छूट चुका है, वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। ललित मोदी ने आगे कहा कि वह भारत लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह शायद इस साल के अंत में या अगले साल की शुरुआत में वापस आएंगे। अक्टूबर में उनकी बेटी को बेटा होने वाला है और उम्मीद है कि सब ठीक रहेगा और वह भारत वापस आ जाऊंगा। गौरतलब है कि ललित मोदी पिछले कई सालों से इंग्लैंड में रह रहे थे। उन्होंने 2010 में भारत छोड़ दिया था। ललित मोदी टैक्स चोरी, धनशोधन और प्रसारण सौदों में हेरफेर के आरोपों के बाद 2010 में भारत छोड़कर लंदन चले गए थे। वह IPL के संस्थापक और तीन साल तक चेयरमैन रहे। बता दें, स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट (SAFEMA) के तहत अपीलीय ट्रिब्यूनल ने 2009 के IPL साउथ अफ्रीका FEMA मामले में ED के ज्यादातर निष्कर्षों और पेनल्टी को रद्द करके ललित मोदी और अन्य अपीलकर्ताओं को बड़ी राहत दी है।

भारत ने हॉकी के टर्फ पर पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी जीत हासिल की

ओमान में मेंस अंडर-18 हॉकी 5s एशिया कप का आयोजन किया जा रहा है। हॉकी के इस फॉर्मेट में एक टीम में 5 ही खिलाड़ी होते हैं। भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में दमदार जीत हासिल की। मस्कट में हुए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 7-4 से हराया। भारत की तरफ से करन गौतम ने हैट्रिक लगाया। उन्होंने मैच के 5वें, 9वें और 19वें मिनट में गोल दागे। करन गौतम के अलावा राहुल यादव ने तीसरे, प्रहलाद राजभर ने 10वें जबकि रोमित पाल और कप्तान केतन कुशवाहा ने 11वें मिनट में गोल दागे। तीन मैचों में भारतीय टीम की यह तीसरी जीत है। इससे पहले टीम ने बांग्लादेश और ओमान को हराया था। 9 पॉइंट के साथ भारत एलिट ग्रुप में पहले स्थान पर है। पाकिस्तान 6 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर है। टॉप-2 पर रहने वाली टीमों के बीच फाइनल होगा। हॉकी5s फील्ड हॉकी का तेज और छोटा वर्जन है, जिसमें हर टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। 4 खिलाड़ी फील्ड पर होते हैं जबकि एक गोलकीपर होता है। खेल दो 10-मिनट के हाफ में होता है और अटैकिंग हाफ में कहीं से भी शूटिंग की जा सकती है। हाफ टाइम ब्रेक दो मिनट का होता है। मैच के पहले दो गोल भारत की तरफ से मारे गए लेकिन पाकिस्तान ने 8वें मिनट तक बराबरी हासिल कर ली।10वें मिनट तक स्कोर 3-3 हो गया लेकिन इसके बाद लगातार तीन गोल मारकर भारत ने स्कोर को 6-3 कर दिया। इसके बाद दोनों टीमों ने 1-1 और गोल दागा। 2026 मेन्स अंडर-18 हॉकी5s एशिया कप का पहली बार आयोजन किया जा रहा है। इसमें कुल सात एशियाई नेशनल टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ओमान, इरान, ईराक और सउदी अरह शामिल हैं। टूर्नामेंट को एशियन हॉकी फेडरेशन ने ऑर्गनाइज किया है। यह टूर्नामेंट 20 जुलाई को इसकी शुरुआत हुई थी और 25 को फाइनल होगा।

मर्दों के सैलून पहुंची रूसी महिला

रूसी ट्रैवल इन्फ्लुएंसर केल्यूबा लिउबोव का दिल्ली के एक मेंस सैलून में फेस मसाज कराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. मात्र 1 डॉलर (₹85) में लिए गए इस देसी अनुभव और भारतीय मेहमाननवाजी की उन्होंने जमकर तारीफ की है.

भारत में नाई की दुकान सिर्फ बाल कटवाने की जगह नहीं होती. यहां कुर्सी पर बैठने के बाद कई बार ग्राहक हेयरकट से ज्यादा फेस मसाज और सिर की मालिश का इंतजार करता है.

कोई एसी सैलून में इस सुख का आनंद लेता है, तो कोई गली के कोने वाली दुकान या पेड़ की छांव में बैठे बार्बर के हाथों का कमाल देखता है. अब भारतीय सैलून का यही देसी अंदाज विदेशियों को भी लुभाने लगा है. रूस की ट्रैवल इन्फ्लुएंसर केल्यूबा लिउबोव ने भी सोचा कि जब भारत आए हैं तो देसी सैलून का अनुभव क्यों न लिया जाए. बस फिर क्या था. वह दिल्ली के एक पुरुषों के सैलून में पहुंच गईं और करीब 1 डॉलर (करीब 85 रुपये) में फेस मसाज करवा डाली. अब उनका यही अनुभव सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में बार्बर पहले बड़े आराम से उनके बाल क्लिप से पीछे बांधता है, फिर क्रीम लगाकर चेहरे की मसाज शुरू कर देता है. इस बीच दुकान में मौजूद लोग भी समझ जाते हैं कि आज का दिन थोड़ा अलग है. कोई आईने के सामने उनके साथ सेल्फी लेने लगता है, तो बाकी ग्राहक भी उत्सुकता से पूरा नजारा देखते रहते हैं. ⊙

देसी बार्बर के हाथों का जादू आया पसंद

वीडियो शेयर करते हुए लिउबोव ने लिखा कि नई दिल्ली में फेस मसाज करवाना अपने आप में एक अलग अनुभव है. उनके चेहरे की मुस्कान भी यही बता रही थी कि देसी बार्बर के हाथों का जादू उन्हें पसंद आया. केल्यूबा इन दिनों भारत घूम रही हैं. उनके इंस्टाग्राम पर ताजमहल, पुरानी दिल्ली की गलियां, गुरुद्वारे, मंदिर और कई मशहूर पर्यटन स्थलों की झलक देखने को मिलती है. उन्होंने अपनी पोस्ट में भारत को सुरक्षित जगह भी बताया है और यहां के लोगों की मेहमाननवाजी की तारीफ की है. ⊙

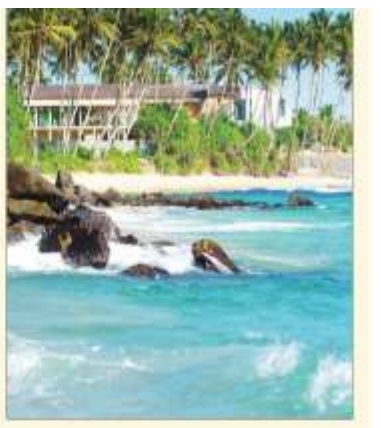

श्रीलंका में भारतीय महिला को लगा कल्चर शॉक

क्या पड़ोसी देश भारत से भी ज्यादा साफ-सुथरा और अनुशासित हो सकता है? सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट के बाद यही सवाल चर्चा में है. भारतीय महिला रुथ डिसूजा प्रभु ने श्रीलंका की यात्रा के अपने अनुभव साझा किए हैं. उन्होंने कहा कि वहां की कुछ बातें देखकर उन्हें 'कल्चर शॉक' लगा और उनका मानना है कि भारत भी अपने पड़ोसी देश से कई बातें सीख सकता है. ⊙

यूएई में बढ़ती गर्मी के बीच पुलिस का सख्त फैसला

कार में बच्चे को अकेला छोड़ा तो होगी जेल और भारी जुर्माना

संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई अपने कड़े नियमों के लिए जाना जाता है. अब यहां बढ़ती गर्मी को लेकर भी एक नियम लागू किया गया है, जो अन्य देशों में देखने को नहीं मिलता है. दरअसल, यहां की पुलिस बढ़ती गर्मी को लेकर सख्त हो गई है और अब पुलिस की ओर से उन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी, जो इस भयानकर गर्मी में बच्चों के अकेले कार में छोड़कर कहीं चले जाते हैं. शारजाह, अजमान, फुजैराह में पुलिस ने बच्चों को खड़ी गाड़ियों के अंदर बिना निगरानी के छोड़ने पर कार्रवाई करने की बात कही है. लीज टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, अभी वहां पारा 45 डिग्री से 50 डिग्री तक पहुंचने का

अनुमान है. इसलिए अधिकारी इस मौसमी खतरे को लेकर सख्त रुख अपना रहे हैं. कानून प्रवर्तन एजेंसियां भीषण गर्मी से होने वाली दुर्घटनाओं और मौतों को रोकने के लिए गहन जागरूकता अभियान चला रही हैं. शारजाह पुलिस के यातायात के डायरेक्टर ब्रिगेडियर खालिद अल-काय ने इस बात पर जोर दिया . ⊙

वैज्ञानिकों ने बनाया फॉर्मूला, जो बताएगा प्रलय की तारीख!

इंसानों का कब धरती से होगा सफाया?

धरती पर इंसानों का अस्तित्व कब तक रहेगा? क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब मानव सभ्यता पूरी तरह खत्म हो जाएगी? ये सवाल सदियों से लोगों को परेशान करते रहे हैं. समय-समय पर दुनिया के खत्म होने यानी प्रलय को लेकर कई भविष्यवाणियां भी सामने आती रही हैं. लेकिन अब कुछ वैज्ञानिकों ने एक ऐसा मैथमेटिकल फॉर्मूला पेश किया है, जो दावा करता है कि वह यह अनुमान लगा सकता है कि इंसान कब तक इस धरती पर रहेंगे. हालांकि यह कोई तय भविष्यवाणी नहीं है, लेकिन इस फॉर्मूले ने वैज्ञानिकों और आम लोगों के बीच बड़ी बहस छेड़ दी है. इसे 'डूम्सडे आर्ग्युमेंट' यानी प्रलय तर्क कहा जाता है.

इस सिद्धांत के पीछे वैज्ञानिकों का तर्क काफी दिलचस्प है. उनका अनुमान है कि मानव इतिहास में अब तक करीब 117 अरब लोग जन्म ले चुके हैं और इस धरती पर जीवन जी चुके हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि आज जीवित इंसान मानव इतिहास की टाइमलाइन में किसी खास या शुरुआती स्थान पर नहीं हैं, बल्कि बिल्कुल सामान्य और रैंडम जगह पर हैं. यहीं से गणित शुरू होता है. वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर अब तक जन्मे 117 अरब लोग मानव इतिहास के कुल लोगों का सिर्फ 5 प्रतिशत हिस्सा हैं, तो 100 प्रतिशत संख्या इससे 20 गुना ज्यादा होगी. इसी आधार पर 117 अरब को 20 से गुणा किया गया. इससे आंकड़ा निकलकर करीब 2.34 ट्रिलियन यानी 2 लाख 34 हजार करोड़ लोगों तक पहुंचता है. ⊙

'आवारापन 2' के गाने से मचा बवाल, अरिजित के संन्यास पर फिर छिड़ी बहस

फिल्म 'आवारापन 2' का बहुप्रतीक्षित टाइटल ट्रैक 'ये आवारापन' मंगलवार को रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। गाने में अरिजित सिंह की आवाज सुनने के बाद फैंस के बीच यह अटकलें तेज हो गईं कि उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास लेने का अपना फैसला वापस ले लिया है और बॉलीवुड में वापसी कर रहे हैं। भावनाओं से भरपूर इस गीत ने श्रोताओं को प्रभावित किया और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर अरिजित के कमबैक को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं।हालांकि, इन अफवाहों के बीच अब अरिजित सिंह की टीम और उनके मैनेजर ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। मीडिया से बातचीत में उनके मैनेजर ने कहा कि 'ये आवारापन' किसी भी तरह से अरिजित की बॉलीवुड में वापसी का संकेत नहीं है। उन्होंने बताया कि यह गाना उन प्रोजेक्ट्स में शामिल है जिनके लिए अरिजित सिंह ने संन्यास की घोषणा से काफी पहले अपनी सहमति दे दी थी। इसलिए वह केवल अपने पुराने वादों और पेशेवर प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहे हैं।मैनेजर ने साफ शब्दों में कहा कि अरिजित सिंह फिलहाल नए प्लेबैक सिंगिंग असाइनमेंट स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गायक अपने पहले से तय किए गए काम पूरे कर रहे हैं और इसे उनकी वापसी के रूप में देखना सही नहीं होगा। इस अटकलों पर काफी हद तक इंडिया के बैनर तले अमाल मलिक ने तैयार हैं। यह गीत फिल्म में

बयान के बाद उनके कमबैक को लेकर चल रही विराम लग गया है।'ये आवारापन' को सोनी म्यूजिक रिलीज किया गया है। गाने का संगीत प्रसिद्ध संगीतकार किया है, जबकि इसके भावपूर्ण बोल रश्मि विराग ने लिखे इमरान हाशमी पर फिल्माया गया है, जो अपने किरदार के भीतर चल रहे भावनात्मक संघर्ष और दर्द को दर्शाता है। गाने को रिलीज के बाद दर्शकों और संगीत प्रेमियों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है।इस गीत की एक खास बात यह भी है कि इसके जरिए अरिजित सिंह एक बार फिर मुकेश भट्ट के प्रोडक्शन हाउस विशेष फिल्म्स के साथ जुड़े हैं। गौरतलब है कि साल 2013 में विशेष फिल्म्स की सुपरहिट फिल्म 'आशिकी 2' के मशहूर गीत 'तुम ही हो' ने अरिजित सिंह को देशभर में नई पहचान दिलाई थी और उन्हें बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय गायकों में शामिल कर दिया था।बता दें कि जनवरी 2026 में अरिजित सिंह ने घोषणा की थी कि वे अब नए प्लेबैक प्रोजेक्ट्स स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा था कि उनका ध्यान अब शास्त्रीय संगीत और स्वतंत्र संगीत निर्माण की ओर अधिक रहेगा। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि वे संगीत से पूरी तरह दूर नहीं होंगे और पहले से किए गए फिल्मी कमिटमेंट्स पूरे करते रहेंगे। इसी कारण आने वाले समय में भी उनके कुछ पहले से रिकॉर्ड किए गए फिल्मी गाने दर्शकों को सुनने को मिल सकते हैं। हाल ही में उनका स्वतंत्र सिंगल 'रैना' भी रिलीज हुआ था, जिसे श्रोताओं ने काफी पसंद किया था।

अखिलेश की हिरासत के बाद लखनऊ में सपा का शक्ति प्रदर्शन कार्यालय के बाहर लगे समर्थन के पोस्टर

NEET-UG 2026 पेपर लीक और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन किया था। इस दौरान अखिलेश यादव सहित कई नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। घटना के बाद लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने पोस्टर और होर्डिंग लगाकर अपने नेता के समर्थन में एकजुटता दिखाई।

दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के बाहर विपक्षी दलों के प्रदर्शन के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को हिरासत में लिए जाने के बाद बुधवार को राजधानी लखनऊ में सियासी हलचल तेज हो गई। समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं और नेताओं ने अखिलेश यादव एवं सांसद डिंपल यादव के समर्थन में बड़े-बड़े पोस्टर और होर्डिंग लगाए। पार्टी कार्यालय के बाहर सुबह से ही समर्थकों की आवाजाही बढ़ी रही और पूरे परिसर में समर्थन के संदेश वाले बैनर लगाए गए। सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कार्यालय के बाहर लगाए गए पोस्टरों के जरिए अखिलेश यादव के प्रति एकजुटता दिखाई। पोस्टरों में पार्टी नेतृत्व के समर्थन और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा का संदेश दिया गया। नेताओं का कहना है कि दिल्ली में हुई कार्रवाई लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है और पार्टी इसका राजनीतिक व लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जारी रखेगी। मंगलवार को अखिलेश यादव कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और विपक्ष के अन्य नेताओं के साथ प्रधानमंत्री आवास, 7 लोक कल्याण मार्ग के बाहर प्रदर्शन में शामिल हुए थे। यह प्रदर्शन संसद मार्च के दौरान छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई और NEET-UG 2026 के कथित पेपर लीक मामले को लेकर आयोजित किया गया था। प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी नेताओं को हिरासत में लेकर वहां से हटा दिया। विपक्षी दलों ने प्रदर्शन के दौरान NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच कराने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई। विपक्ष का आरोप है कि परीक्षा प्रणाली में हुई गंभीर चूक से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है और सरकार इस मुद्दे पर जवाब देने से बच रही है। दिल्ली की घटना के बाद लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी मुख्यालय पर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गईं। पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता लगातार कार्यालय पहुंचते रहे। समर्थकों ने अखिलेश यादव और डिंपल यादव के समर्थन में नारे लगाए और पोस्टर अभियान चलाकर पार्टी नेतृत्व के साथ एकजुटता का संदेश दिया। सपा नेताओं ने कहा कि विपक्ष की आवाज दबाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, जबकि शांतिपूर्ण विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है। वहीं, राजधानी लखनऊ में पार्टी कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर और होर्डिंग को सपा के शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। दिल्ली की घटना के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस मुद्दे को लेकर सियासी बयानबाजी तेज होने के आसार हैं।

विवाहिता की संदिग्ध मौत, परिजनों ने पति पर हत्या का लगाया आरोप

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

लखनऊ के ठाकुरगंज में शादी के 6 साल बाद एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिवार का कहना है कि दामाद ने मंगलवार शाम फोन करके बताया बेटी ने जहर खा लिया है। जब परिवार लखनऊ पहुंचा तो देखा सिर व नाक से खून निकल रहा था। परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही सूरज आरती के साथ मारपीट करता था और उसे प्रताड़ित करता था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आजाद नगर, रामनगर माल निवासी परमेश्वर ने बताया, उन्होंने अपनी बेटी आरती की शादी 8 दिसंबर 2020 को ठाकुरगंज के राजा विहार निवासी सूरज उर्फ गोलू से की थी। सूरज सफाईकर्मी है। दंपती के दो बच्चे हैं, जिनमें चार वर्षीय बेटा शिवांश और पांच महीने की एक बेटी है। परमेश्वर ने बताया कि मंगलवार शाम करीब 6 बजे सूरज का फोन आया। उसने कहा कि आरती की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। सूचना मिलते ही परिवार माल से लखनऊ के लिए रवाना हो गया। परिजनों का आरोप है कि पहले उन्हें बताया गया कि आरती को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, लेकिन वहां पहुंचने पर पता चला कि उसे बलरामपुर अस्पताल ले जाया गया है। जब परिवार बलरामपुर अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टरों ने आरती को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका की बड़ी बहन सुमन ने बताया कि वह बालू अड्डा क्षेत्र में रहती हैं, लेकिन घटना की जानकारी उन्हें सूरज ने नहीं दी। उनका कहना है कि सूरज लगातार परिवार को गुमराह करता रहा और सही जानकारी नहीं दी। जब परिवार अस्पताल पहुंचा तो आरती के सिर और नाक से खून निकल रहा था। परिजनों का आरोप है कि आरती की पीट-पीटकर हत्या की गई है।

लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में 15 साल के बच्चे के साथ मारपीट का मामला आया सामने

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में 15 साल के बच्चे के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि अस्पताल में तैनात सिक्योरिटी गार्डों ने बच्चे की बेरहमी से पिटाई कर दी। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें गार्ड मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद बाद मामला स्वास्थ्य विभाग तक पहुंच गया। डिप्टी सीएम एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने घटना का संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने अस्पताल प्रशासन से पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक रात दो बजे मदेयगंज चौकी से पुलिस कुल 5 लोगों को मेडिकल कराने लाई थी। इनमें 2 लोगों का मेडिकल हो गया था, जबकि 3 का पेपर न होने के चलते होना बाकी रह गया। पुलिस इन्हें इमरजेंसी में भी छोड़कर चली गई। इस बीच सुबह किसी बात को लेकर इन तीनों का विवाद EMO डॉ. सुरूर अली से हो गया। इसके बाद मौके जब गार्ड्स पहुंचे तो कहासुनी बढ़ गई। देखते ही देखते मारपीट होने लगी। डिप्टी सीएम ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि उन्होंने महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद मौके पर जाकर जांच करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तीन दिन के अंदर जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा है। उन्होंने लिखा कि बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ में मारपीट से संबंधित

वीडियो का संज्ञान लेते हुए महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को प्रकरण की जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और तीन दिन के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इस मामले के बलरामपुर अस्पताल के निदेशक डॉ.विवेक गुप्ता ने बताया कि घटना को लेकर CCTV फुटेज खंगाले जा रहे है। शासन की तरफ से जांच के आदेश भी दिए जा चुके है। निष्पक्ष जांच के आधार पर रिपोर्ट तैयार होगी और फिर उसे शासन को भेजा जाएगा। तय समय से पहले ही जांच पूरी करने की कोशिश की जाएगी।

लखनऊ में बुधवार को बदला मौसम का मिजाज

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

राजधानी लखनऊ में बुधवार (22 जुलाई) को मौसम का मिजाज बदला हुआ है। दोपहर करीब 12:30 बजे उमस भरी गर्मी के बीच तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, लेकिन अधिक नमी के कारण लोगों को 41 डिग्री जैसी गर्मी महसूस हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार दोपहर से शाम तक शहर के कई इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। मंगलवार को लखनऊ में 8.9 मिमी बारिश दर्ज, सामान्य से 57% ज्यादा; मानसून सीजन में (1 जून-2026) अब तक 159.1 मिमी बारिश, फिर भी 36% की कमी है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश के अनुसार दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे के बीच लखनऊ में कई दौर की बारिश हो सकती है। इस दौरान गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। शाम 5 बजे तक बारिश की संभावना 60% तक पहुंच सकती है। हालांकि शहर में हल्की बारिश हो रही है, लेकिन हवा में नमी अधिक होने की वजह से लोगों को उमस से राहत नहीं मिल रही। तापमान 33 डिग्री होने के बावजूद 41 डिग्री दर्ज किया गया, जिससे दिनभर चिपचिपी गर्मी बनी हुई है। शहर में बुधवार को करीब 21 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। बारिश के दौरान कुछ इलाकों में तेज हवा के साथ पेड़ों की टहनियां टूटने और जलभराव की स्थिति भी बन सकती है। ऐसे में वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बीते मंगलवार को लखनऊ का अधिकतम तापमान 32.3°C दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.3°C कम रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 25°C रिकॉर्ड हुआ, जो सामान्य से 0.7°C कम है। सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक शहर में 0.2 मिमी बारिश दर्ज की गई। पूर्वानुमान के अनुसार गुरुवार से रविवार तक भी राजधानी में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। शुक्रवार को हल्की बारिश, जबकि रविवार को गरज-चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। मानसूनी गतिविधियां सक्रिय रहने से अगले कुछ दिनों तक तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है।

लखनऊ में कांग्रेस का प्रदर्शन,

बैरिकेडिंग तोड़ 5-कालिदास मार्ग की ओर बढ़े कार्यकर्ता

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

लखनऊ में बुधवार को कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कार्यालय से लाठी लेकर 5-कालिदास मार्ग की ओर कूच किया। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने तीन रास्तों पर 4 लेयर की बैरिकेडिंग की।प्रदर्शनकारियों ने पहली बैरिकेडिंग तोड़ दी। करीब 100 मीटर तक आगे बढ़ गए। पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई। दूसरी बैरिकेडिंग पर चढ़े पूर्व एमएलसी दीपक सिंह समेत अन्य कार्यकर्ताओं को पुलिस ने धक्का देकर गिरा दिया। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पगड़ी बांधकर बैरिकेडिंग के पास धरने पर बैठ गए। पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर ईको गार्डन भेजा। दरअसल, मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी व प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीएम आवास के पास धरना-प्रदर्शन किया था। इसके जवाब में भाजपा ने लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने का ऐलान किया था। इसके जवाब में कांग्रेसियों ने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की अगुवाई में बैठक की। उसमें भाजपा को जवाब में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया।

मौरावां में भाजपा का बूथ अध्यक्ष सम्मेलन, 496 बूथ अध्यक्षों को दिया चुनावी मंत्र

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उन्नाव के पुरवा विधानसभा क्षेत्र में मौरावां नगर पंचायत स्थित रामलीला मैदान में बुधवार शाम भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष सम्मेलन आयोजित किया गया। शाम करीब चार बजे शुरू हुआ कार्यक्रम लगभग एक घंटे तक चला। इसमें पुरवा विधानसभा के 496 बूथ अध्यक्षों ने भाग लिया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाना और आगामी चुनावों की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा करना था। कार्यक्रम में हरदोई के पूर्व जिलाध्यक्ष कृष्ण शास्त्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। पुरवा विधायक अनिल सिंह और भाजपा जिलाध्यक्ष अनुराग अवस्थी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बूथ अध्यक्षों की भूमिका को संगठन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बताया। नेताओं ने कार्यकर्ताओं से प्रत्येक बूथ पर संगठन को सक्रिय रखने, सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने और मतदाताओं से नियमित संपर्क बनाए रखने का आह्वान किया। सम्मेलन के दौरान बूथ प्रबंधन, सदस्यता अभियान, संगठनात्मक गतिविधियों और आगामी

चुनावी रणनीति पर भी चर्चा हुई। नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि बूथ स्तर पर मजबूत संगठन ही चुनावी सफलता की कुंजी है और प्रत्येक कार्यकर्ता को पूरी सक्रियता के साथ अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। इस अवसर पर विधायक अनिल सिंह ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि देश विरोधी ताकतें छात्रों की आड़ लेकर माहौल खराब करने का प्रयास कर रही हैं। उन्होंने दावा किया कि कुछ प्रदर्शनों में "भारत तेरे टुकड़े होंगे" जैसे नारे लगाए गए, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। विधायक ने कहा कि ऐसे मामलों में कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और देश विरोधी गतिविधियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रधान संघ अध्यक्ष प्रतिनिधि पुरवा अमित त्रिवेदी, चेयरमैन मौरावां कुंवर विवेक सेठ, ब्लॉक प्रमुख असोहा आनंद गुप्ता, महेन्द्र लोधी, रियाजुल हसन, पूर्व मंडल अध्यक्ष शुभम श्रीवास्तव, आशिक अली, जैनुल आब्दीन, आशीष साहू, दुधे लाल साहू, रिजवान कुरैशी समेत आदि पदाधिकारी और 496 बूथ अध्यक्ष मौजूद रहें।

आदर्श नगर नहर पटरी मार्ग निर्माण का हुआ शुभारंभ

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उन्नाव शहर के आदर्श नगर क्षेत्र में लंबे समय से प्रतीक्षित नहर पटरी मार्ग का निर्माण बुधवार को शुरू हुआ। सदर विधायक पंकज गुप्ता ने एनएच-25 से आदर्श नगर नहर पटरी तक बनने वाले मिसिंग लिंक मार्ग का शिलान्यास और भूमिपूजन किया। यह कार्यक्रम वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधि-विधान से संपन्न हुआ। विधायक पंकज गुप्ता ने शिलान्यास समारोह में बताया कि इस रास्ते के निर्माण से आदर्श नगर और आसपास के हजारों निवासियों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्रवासी कई सालों से इस सड़क के निर्माण की मांग कर रहे थे, जो अब पूरी हो रही है। विधायक ने आगे कहा कि नई सड़क से लोगों को जाम और खराब रास्तों की समस्या से निजात मिलेगी, जिससे आवागमन अधिक सुगम और सुरक्षित हो जाएगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि प्रदेश सरकार जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आधारभूत सुविधाओं के विस्तार पर निरंतर कार्य कर रही है। पंकज गुप्ता ने विश्वास व्यक्त किया कि यह मार्ग क्षेत्र के विकास को नई गति प्रदान करेगा और स्थानीय नागरिकों के जीवन स्तर में भी सकारात्मक बदलाव लाएगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण तरीके से और निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए।

गंगाघाट रेलवे स्टेशन पर निर्माण कार्य तेज

उन्नाव में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत गंगाघाट रेलवे स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्यों का बुधवार दोपहर करीब दो बजे निरीक्षण किया गया। एईएक्सएन गतिशक्ति डॉ. एस.सी. श्रीवास्तव ने यह निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने विकास कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता और समयसीमा की जानकारी ली। इस दौरान जेई (आईओडब्ल्यू) अभिषेक मिश्रा भी उपस्थित थे। डॉ. श्रीवास्तव ने निर्माण एजेंसी और रेलवे अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने जोर दिया कि अमृत भारत स्टेशन योजना का लक्ष्य यात्रियों को आधुनिक और बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है, इसलिए निर्माण की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। निरीक्षण के दौरान, अधिकारियों ने स्टेशन भवन, प्लेटफॉर्म क्षेत्र, यात्री सुविधाओं, सौंदर्यीकरण सहित अन्य निर्माणाधीन कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। निर्माण एजेंसी ने बताया कि कार्य तेजी से चल रहा है और अधिकांश परियोजनाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ रही हैं। डॉ. एस.सी. श्रीवास्तव ने अब तक हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य अच्छी गति से चल रहा है और यदि यही रफ्तार बनी रही तो वर्ष 2026 के अंत तक परियोजना का अधिकांश हिस्सा पूरा कर लिया जाएगा। इससे गंगाघाट रेलवे स्टेशन का स्वरूप बदल जाएगा और यात्रियों को आधुनिक सुविधाओं का लाभ मिलेगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत गंगाघाट रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य जारी हैं। इनमें स्टेशन भवन का उन्नयन, बेहतर प्रतीक्षालय, आधुनिक शौचालय, दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाएं, आकर्षक प्रवेश द्वार, बेहतर प्रकाश व्यवस्था, यात्री सूचना प्रणाली, पार्किंग और स्टेशन परिसर का सौंदर्यीकरण शामिल हैं। अधिकारियों ने निर्माण एजेंसी को सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखने और गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने के निर्देश भी दिए। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, परियोजना पूरी होने के बाद गंगाघाट रेलवे स्टेशन यात्रियों के लिए एक आधुनिक और सुविधाजनक केंद्र बन जाएगा।

उन्नाव में जर्जर भवनों का सर्वे तेज, 90 प्रतिशत कार्य पूरा

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उन्नाव में बारिश के मौसम में जर्जर भवनों से होने वाले हादसों को रोकने के लिए नगर पालिका परिषद ने सर्वे अभियान तेज कर दिया है। दो जुलाई को नवीन यातायात पुल स्थित सीताराम कॉलोनी में एक जर्जर मकान का छज्जा गिरने से दो लोग घायल हो गए थे। इस घटना के बाद पालिका प्रशासन ने जिले के सभी वार्डों में जर्जर भवनों की पहचान के लिए विशेष सर्वे शुरू किया था। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी डॉ. राजेश कुमार ने बताया कि तीन जुलाई को जर्जर भवनों के सर्वे के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया था। यह टीम लगातार वार्डवार निरीक्षण कर पुराने मकानों, व्यावसायिक भवनों और लंबे समय से बंद पड़े भवनों की स्थिति का आकलन कर रही है। अब तक पालिका क्षेत्र के 28 वार्डों में से लगभग 25 वार्डों का सर्वे पूरा हो चुका है। शेष सात वार्डों में सर्वे का कार्य तेजी से जारी है। कुल मिलाकर, करीब नब्बे प्रतिशत सर्वे कार्य पूरा कर लिया गया है। सर्वे के दौरान भवनों की दीवारों में आई दरारें, झुके हुए हिस्से, कमजोर छत, जर्जर छज्जे और अन्य संरचनात्मक कमियों की बारीकी से जांच की जा रही है। जिन भवनों से आमजन को खतरा होने की आशंका है, उन्हें सूचीबद्ध किया जा रहा है। विशेष रूप से मुख्य मार्गों, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों के आसपास स्थित खतरनाक भवनों को प्राथमिकता दी जा रही है। अधिशासी अधिकारी ने बताया कि सर्वे रिपोर्ट तैयार होने के बाद जर्जर भवनों की सूची सार्वजनिक की जाएगी। साथ ही संबंधित भवन स्वामियों को नोटिस जारी कर निर्धारित समय सीमा के भीतर स्वयं भवन के जर्जर हिस्से को हटाने या सुरक्षित कराने के निर्देश दिए जाएंगे। यदि तय अवधि में भवन स्वामी कार्रवाई नहीं करते हैं, तो इसकी रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजी जाएगी। इसके बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

उच्चस्तरीय जांच की मांग, कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उन्नाव में भारतीय किसान यूनियन (सावित्री) के कार्यकर्ताओं ने अवैध बूचड़खानों और अवैध खनन के खिलाफ प्रदर्शन कर उच्चस्तरीय जांच की मांग की। संगठन ने आरोप लगाया कि शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है और चेतावनी दी कि मांगें पूरी न होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। ज्ञापन में इंडाग्रो फूड प्राइवेट लिमिटेड और जे.एस. फूड प्राइवेट लिमिटेड सहित अन्य बूचड़खानों का उल्लेख किया गया है। संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष सावित्री सिंह ने बताया कि इन बूचड़खानों से निकलने वाले अपशिष्ट और दुर्गंध से आसपास के निवासियों को भारी परेशानी हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। संगठन ने प्रशासन से मांग की है कि आबादी के बीच संचालित अवैध बूचड़खानों को तत्काल बंद किया जाए या उन्हें आबादी से दूर स्थानांतरित किया जाए। इसके साथ ही, प्रदूषण नियंत्रण मानकों का उल्लंघन करने वाले संचालकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने की भी मांग की गई। भारतीय किसान यूनियन (सावित्री) ने गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त बनाए रखने की भी मांग उठाई। संगठन का कहना है कि यदि औद्योगिक इकाइयों और बूचड़खानों से निकलने वाले अपशिष्ट पर प्रभावी नियंत्रण नहीं किया गया, तो पर्यावरण को गंभीर नुकसान होगा। इसके अतिरिक्त, संगठन ने पुरवा तहसील के ऊंचगांव सानी गांव में अवैध खनन का गंभीर आरोप लगाया है।

श्रावण मास की तैयारियों का प्रशासन ने लिया जायजा, बक्सर घाट पर सुरक्षा और सुविधाओं का निरीक्षण

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

30 जुलाई 2026 से शुरू हो रहे पवित्र श्रावण मास को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में बुधवार को बीघापुर तहसील प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने क्षेत्र के प्रमुख धार्मिक स्थल बक्सर घाट का संयुक्त निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।निरीक्षण के दौरान उपजिलाधिकारी बीघापुर आनंद कुमार नायक, क्षेत्राधिकारी बीघापुर मधुप नाथ मिश्रा तथा नायब तहसीलदार सुमेरपुर अवनीश मिश्रा मौजूद रहे। अधिकारियों ने घाट परिसर, श्रद्धालुओं के आवागमन मार्ग, सुरक्षा व्यवस्था, साफ-सफाई और अन्य आवश्यक सुविधाओं का निरीक्षण किया। श्रावण मास में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना को देखते हुए विभिन्न व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई।अधिकारियों ने संबंधित विभागों और कर्मचारियों को निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। घाट क्षेत्र में साफ-सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, बैरिकेडिंग, सुरक्षा प्रबंध और भीड़ नियंत्रण की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए भी आवश्यक इंतजाम करने पर जोर दिया गया।निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने कहा कि श्रावण मास धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा-अर्चना एवं जलाभिषेक के लिए घाटों और मंदिरों में पहुंचते हैं। ऐसे में कानून-व्यवस्था बनाए रखना और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है।प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को सभी तैयारियां समय से पूरी करने के निर्देश दिए हैं, ताकि श्रावण मास के दौरान श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम वातावरण मिल सके। अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से भी सहयोग की अपील की और कहा कि किसी भी समस्या की सूचना तत्काल प्रशासन को दें।श्रावण मास के मद्देनजर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के साथ-साथ धार्मिक आयोजनों की नियमित निगरानी भी की जाएगी, ताकि सभी कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सकें।

संसद में NEET, छात्रों के आंदोलन और पुलिस कार्रवाई पर घमासान अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा

NEET-UG पेपर लीक मामले को लेकर देशभर में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। 20 जुलाई को जंतर-मंतर से संसद मार्च के दौरान पुलिस कार्रवाई के बाद यह मुद्दा और गरमा गया। मॉनसून सत्र में विपक्ष इसी मुद्दे पर सरकार को लगातार घेर रहा है। मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली, युवाओं के भविष्य और कानून-व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर सरकार को लगातार घेरने का प्रयास कर रहा है।

संसद के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन बुधवार को लोकसभा और राज्यसभा में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने NEET-UG पेपर लीक मामले, छात्रों के आंदोलन पर हुई पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरते हुए जवाबदेही की मांग की। इन मुद्दों को लेकर सदन के भीतर और बाहर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज रही।समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने संसद परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह केवल किसी राजनीतिक दल का मामला नहीं है, बल्कि देश के करोड़ों युवाओं और छात्रों के भविष्य से जुड़ा गंभीर प्रश्न है। उन्होंने कहा कि जब छात्र अपने अधिकारों और भविष्य की सुरक्षा को लेकर आवाज उठा रहे हैं, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनकी बात सुनी जानी चाहिए। सरकार का दायित्व है कि वह छात्रों की चिंताओं को गंभीरता से ले और उनके सवालों का जवाब दे।अखिलेश यादव ने 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर से निकाले गए छात्र मार्च का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों और युवाओं पर हुई पुलिस कार्रवाई बेहद चिंताजनक है। उनका कहना था कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगें रखने वाले लोगों के साथ कठोरता नहीं बरती जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, जबकि उन्हें संवाद और चर्चा के माध्यम से समाधान देने की आवश्यकता है।इस दौरान अखिलेश यादव ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि सदन में युवाओं और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि छात्रों की समस्याओं और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को संसद में पर्याप्त महत्व क्यों नहीं दिया जा रहा है। उनके बयान ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस को जन्म दे दिया।गौरतलब है कि 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के बैनर तले जंतर-मंतर से संसद की ओर एक बड़ा मार्च निकाला गया था। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र और युवा शामिल हुए थे, जो NEET पेपर लीक मामले में जवाबदेही और कार्रवाई की मांग कर रहे थे। संसद की ओर बढ़ते समय प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग किया।इस घटना के विरोध में 21 जुलाई को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठे। दोनों नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए छात्रों के साथ एकजुटता दिखाई। बाद में दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया, हालांकि कुछ समय बाद उन्हें रिहा कर दिया गया।मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली, युवाओं के भविष्य और कानून-व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर सरकार को लगातार घेरने का प्रयास कर रहा है। वहीं सरकार का आरोप है कि विपक्ष राजनीतिक लाभ के लिए इन मुद्दों का इस्तेमाल कर रहा है और सदन की कार्यवाही में व्यवधान डाल रहा है। आने वाले दिनों में इन मुद्दों को लेकर संसद और राजनीतिक मंचों पर बहस और तेज होने की संभावना है।

बदमाश शंकर पांडे की संपत्ति होगी कुर्क! पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी

गाजीपुर के चर्चित सचिन चौरसिया अपहरण कांड में फरार चल रहे एक लाख रुपए के इनामी और कटरा गैंग के सरगना शंकर पांडे के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। बुधवार को कोतवाली पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर शंकर पांडे के गौशाबाद स्थित आवास पर मुनादी कराई और निर्धारित समय के भीतर अदालत में पेश होने की चेतावनी दी। पुलिस के मुताबिक, यदि आरोपी कोर्ट में पेश नहीं होता है तो उसकी चल और अचल संपत्ति कुर्क की जाएगी। पुलिस के मुताबिक, अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम के आदेश के बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 84 के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस टीम ने आरोपी के घर पहुंचकर लाउडस्पीकर के माध्यम से न्यायालय का आदेश पढ़कर सुनाया और स्थानीय लोगों को भी इसकी जानकारी दी। मुनादी के दौरान कहा गया कि यदि आरोपी यदि न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है तो उसकी चल और अचल संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। दरअसल, यह कार्रवाई 5 सितंबर 2024 को हुए चर्चित व्यापारी सचिन चौरसिया अपहरण और मारपीट मामले में की जा रही है। आरोप है कि शंकर पांडे ने अपने साथियों के साथ मिलकर सचिन चौरसिया का स्कॉर्पियो से अपहरण किया था और पीड़ित के साथ मारपीट भी की थी। इस मामले में थाने में पहले से मुकदमा दर्ज है। लगातार अदालत में पेश न होने के कारण उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट भी जारी किया जा चुका है। विशेष लोक अभियोजक अखिलेश सिंह के मुताबिक, इस मामले में हाल ही में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए एक लाख रुपए के इनामी कमलेश बिंद का नाम भी सामने आया था।

नेशनल हाईवे पर एक कार अनियंत्रित होकर नाले में गिर गई

बाराबंकी में एक बड़ा हादसा होने से बच गया। नेशनल हाईवे पर एक कार अनियंत्रित होकर नाले में गिर गई। इसी दौरान वहां से निकल रही एसडीएम ने पुलिस को सूचना दी, इससे चालक को बचाया जा सका। बाराबंकी में बांदा–बहराइच नेशनल हाईवे पर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक अनियंत्रित कार सड़क किनारे नाले में जा गिरी। यह घटना रामनगर थाना क्षेत्र के ग्राम सुरवारी के पास की है। जहां कार चालक अचानक गाड़ी पर से नियंत्रण खो बैठा और वो नाले में जा गिरी। संयोग की बात है कि उसी वक्त उप जिलाधिकारी यानी एसडी रामनगर आकांक्षा गुप्ता मौके से गुजर रही थीं। उन्होंने तुरंत वाहन रुकवाकर स्थिति का जायजा लिया और पुलिस को सूचना दी। इससे बड़ा हादसा होने से बच गया। इसके बाद प्रशासन की तत्परता से मौके पर तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया गया। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले रामनगर से बांदा–बहराइच नेशनल हाईवे गुजरता है। यहां पर अक्सर गाड़ियों की खूब आवाजाही रहती है। बुधवार को भी ऐसा ही चल रहा था। इस बीच एक कार अनियंत्रित होकर नाले में चली गई। एसडीएम वहां से गुजर रही थीं, इसलिए बड़ा हादसा होने से बच गया। सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक रामनगर पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पुलिसबल ने चालक को सुरक्षित गाड़ी से बाहर निकाला और उससे पूछताछ की। पुलिस की पूछताछ में चालक ने बताया कि यह वाहन निजी है और पहले अनुबंध पर संचालित होता था, जो एक माह पहले समाप्त हो चुका है। वह कार को लखनऊ से बहराइच लेकर जा रहा था, तभी यह हादसा पेश आ गया। राहत की बात यह रही कि कार में चालक के अलावा कोई अन्य सवार नहीं था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, जबकि समय रहते कार्रवाई से एक बड़ा हादसा होने से बच गया।

कोर्ट में मृतक की पत्नी प्रेमी और प्रेमी के भाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

आगरा के थाना ताजगंज क्षेत्र के वर्ष 2021 के चर्चित फैक्ट्री संचालक नरेश कुमार हत्याकांड में पांच साल बाद अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए मृतक की पत्नी प्रमिता उर्फ प्रेमिता, उसके प्रेमी रविकांत राजपूत और रविकांत के भाई शशिकांत राजपूत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट शिव कुमार ने तीनों दोषियों पर कुल 2.80 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला 8 जून 2021 का है। सिद्धार्थनगर निवासी सुरेश चंद ने ताजगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि सुबह फोन पर सूचना मिली कि उनके बेटे नरेश कुमार की हत्या कर शव को घर के पीछे खाली प्लॉट में बोरे में बंद कर फेंक दिया गया है। मौके पर पहुंचने पर नरेश का शव बोरे में मिला। उन्होंने शुरुआत से ही बहू प्रमिता पर हत्या की साजिश का शक जताया था। पुलिस जांच में सामने आया कि प्रमिता के थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के नगला केवल निवासी रविकांत राजपूत से करीबी संबंध थे। कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) और मोबाइल की जांच में दोनों के बीच लगातार संपर्क के प्रमाण मिले। जांच आगे बढ़ी तो रविकांत के भाई शशिकांत की भूमिका भी सामने आई। इसके बाद पुलिस ने दोनों भाइयों को मामले में आरोपी बनाया और हत्या के साथ एससी/एसटी एक्ट की धाराएं भी जोड़ीं। विवेचना के दौरान पुलिस को घर के कमरे की दीवार और फर्श पर खून के निशान मिले। घटनास्थल से खून लगी ईंट, शराब की बोतल और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य बरामद किए गए। जांच में सामने आया कि नरेश की हत्या घर के अंदर की गई और बाद में शव को बोरे में बांधकर मकान के पीछे खाली पड़े प्लॉट में फेंक दिया गया। मुकदमे के दौरान मृतक की बेटी लवली की गवाही अभियोजन के लिए सबसे अहम साबित हुई। उसने अदालत को बताया कि घटना की रात माता-पिता के बीच झगड़ा हो रहा था। उसकी मां ने तीनों भाई-बहनों को मोबाइल और कोल्ड ड्रिंक देकर कमरे में बंद कर दिया था। बाहर से कुंडी लगी होने के कारण वे बाहर नहीं निकल सके। रात में मारपीट की आवाजें सुनाई देती रहीं। देर रात करीब 3 बजे उसके दरवाजा खटखटाया मम्मी ने दरवाजा खोला था। जब वह बाहर निकली तो कमरे में खून के निशान, दीवार पर नाखून के निशान और मां को रात में नहाते हुए देखा।